due to imposition of export duty on tea in 1977, and (iii) over-all lack of buoyancy in the export trade. The steps taken by Government in the wake of declining exports in 1978, include (i) the abolition of export duty on tea with effect from 14-2-1979, (ii) re-introduction in January, 1979 of the system of refund of additional excise duty on packet tea exports, (iii) placing the import of tea bagging machines under OGL, (iv) the reduction in the import duty on tea bagging machinery from 75 per cent to 25 percent w.e.f. 18--80, and (v) enhancement of the rate of cash compensatory support from 10 per cent to 12½ per cent on packet tea and tea bags from April, 1979. In addition, the Tea Board's office abroad continue to undertake various promotional measures name generic promotion, uni-national promotion, participation in trade fairs, exhibitions etc.

Working of Sick Textile Units under National Textile Corporation

3949. SHRI S. M. KRISHNA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what measures have been taken by Government to revamp the working of the various sick textile units at present run by the National Textile Corporation;

(b) whether in view of the present trends in the textile industry, Government have considered the desirability of taking up the manufacture of man-made fabrics in some of these mills like terrycot, terene and other types of blended fabrics;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) what steps Government propose to take in the matter with a view to ensure profitable working of the National Textile Corporation?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (d). Some of the important steps taken and/or being taken to improve the working of NTC mills and to make them viable are as follows:—

(i) modernisation/renovation of the machinery;

(ii) rationalisation of work load and labour force;

(iii) bulk procurement of raw material on centralised basis;

(iv) diversification in the pattern of production; and

(v) installation of diesel generating sets in some of the units to overcome power shortages.

(b) Terrycot and blended fabrics are already being produced in some of the NTC mills where necessary facilities are available.

(c) Does not arise.

Golds output of Kolar Gold Fields

3950. SHRI S M. KRISHNA. Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the present gold output of the Kolar Gold Fields;

(b) whether it has been explored at any stage that the mining of lower grade ore will yield more profitable results: if not, the reasons therefor and

(c) what other measures are proposed to be taken to raise the output and create more employment potential for the Local miners who had lost their jobs on account of retrenchment some time back?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) The output of gold during 1979-80 was 1560 kgs. The output during the first quarter of 1980-81 was about 375 kgs.

(b) Intensive exploration work has been in progress for the discovery of oreshoots in the existing mines and in the Kolar Schist Belt. Exploitation of lower grade ore has become economically viable consequent to the recent increase in the price of gold. To take advantage of this the Company has drawn up plans for progressively higher utilisation of lean grade ore.

(c) Consequent upon the closure of work in certain uneconomic sections of the mines in 1959, the services of some of the employees were dispensed with under a scheme of voluntary retirement. The exploitation of lean ores, the implementation of the Scheelite Recovery Project and the expansion of the activities of the Mine Contract Division are expected to create additional employment potential.

इस्पात का आयात

3951. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस्पात आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले इस्पात का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) इस्पात का आयात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) . जी, हां ।

(ख) और (ग) देशीय उपलब्धी और मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए वर्ष 1980-81 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को 6.9 लाख टन इस्पात का बफर आयात करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है ? इसके अलावा वर्तमान आयात नीति के अधीन सेल अलग-अलग ग्राहकों की मांग के आधार पर "बैक-टू-बैक" आयात करने का कार्य भी करेगी । सेल बफर तथा बैक-टू-बैक आधार पर जो आयात करेगी उसकी लागत लगभग 550 करोड़ रुपये होगी लेकिन यह उसके पास पंजीकृत मांग पर निर्भर करेगा । आयात की वर्तमान नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों तथा निर्यात घरानों को भी आयात करने की अनुमति दी गई है ।

लघु उद्योगों में बनी वस्तुओं का निर्यात

3952. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लघु उद्योगों से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को लागू करने के फलस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) . (क) और (ख) लघु उद्योग उत्पादों को देश के निर्यात ढांचे के पहले ही एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और 1978-79 में इनके निर्यात कुल निर्यातों का लगभग 16.44 प्रतिशत रहे। लघु उद्योग विकास निगम अपने लघु उद्योग सेवा संस्थान व्यवस्था के माध्यम से लघु उद्योगों के निर्यातों के संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाता है । इनमें शामिल है : प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों व कार्यशालाओं आदि का आयोजन; सूचना तथा परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था; निर्यात विपणन समूहों सार्थसंघों का सवर्धन; व्यापार विकास प्राधिकरण तथा अन्य निर्यात संगठन संगठनों के पास सूचीबद्ध किये जाने के लिए निर्यात योग्य एककों का पता लगाना; और निर्यात संवर्धन संगठन के सहयोग से व्यापार मेलो व प्रदर्शनियो तथा अन्य बाजार तथा बिक्री संवर्धन गतिविधियों में माल लेने के लिए निर्यात अभिमुख लघु एककों की सहायता तथा उसका मार्गदर्शन ।

लघु उद्योग विकास संगठन के अलावा लघु उद्योगों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए अन्य अनेक संगठनों जैसे कि व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय राज्य व्यापार निगम, परियोजना तथा उपस्कर निगम, निर्यात संवर्धन परिषदों के भी अपने कार्यक्रम हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय ने केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न निर्यात संवर्धन संगठनों के बीच कारगर संपर्क स्थापित करने तथा लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यातों के विकास के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार करने के उद्देश्य से अपनी संकल्प सं० 17/(20)/80 ई० पी० एस० दिनांक 4-6-1980 के अन्तर्गत विकास